ARUN COMPUTER & IT

📖 PDF Study Material

For PGDCA & DCA Examination

IT Trends & Technologies

Unit-1

विषय सूची:

- E-governance, e-democracy
- PPP model, MPonline, UIDI,& Aadhar
- Cyber Crime, spyware, malware, spam mail, logic bomb, phishing,

हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करें

Latest version available only at: www.hamararewa.in

Prepared & Updated by Arun Computer

© 2026 All Rights

Syllabus- Unit-1- E-governance, e-democracy, Government efforts to encourage citizen participation, PPP model, /e-governance websites & services, MPONLINE services, UIDI &Aadhar, /e-governace mobile apps like UMANG, Digital Lockar , ldigital Library,

Itroduction to cyber crime, types of attacks like spyware, malware, spam mail, logic bombs, denial of service, tyupes of cyber crime like email fraud, phishing, spoofing, hacking, identity theft.

E-governance, e-democracy

ई-गवर्नेंस

ई-गवर्नेंस का अर्थ है सरकारी सेवाओं को ICT (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) के माध्यम से नागरिकों तक पहुँचाना। इससे सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी कम होती है। यह पारदर्शिता, दक्षता और सुविधा प्रदान करता है।
उदाहरण: ऑनलाइन आयकर भरना, डिजिटल लोक सेवा केंद्र।

ई-गवर्नेंस के प्रकार (G2C, G2B, G2G)

G2C (सरकार से नागरिक) में पंजीकरण, राशन कार्ड जैसी सेवाएँ शामिल हैं।
G2B (सरकार से व्यवसाय) टैक्स भरने और लाइसेंस से संबंधित है।
G2G (सरकार से सरकार) विभिन्न सरकारी विभागों के बीच डेटा साझा करता है।
ये तीनों मॉडल ई-गवर्नेंस की रीढ़ हैं।

ई-डेमोक्रेसी

ई-डेमोक्रेसी, नागरिकों की भागीदारी का डिजिटल माध्यम है।
ई-डेमोक्रेसी से नागरिक ऑनलाइन माध्यमों से नीति-निर्माण में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें ई-वोटिंग, ऑनलाइन परामर्श और डिजिटल याचिकाएँ शामिल हैं। इसका उद्देश्य सरकार को अधिक जवाबदेह और समावेशी बनाना है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बढ़ावा देता है।

ई-गवर्नेंस और ई-डेमोक्रेसी में अंतर

ई-गवर्नेंस सेवा वितरण (सुविधा) पर केंद्रित है, जबकि ई-डेमोक्रेसी नागरिकों के निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी (सशक्तिकरण) पर केंद्रित है। ई-गवर्नेंस टॉप-डाउन मॉडल है, वहीं ई-डेमोक्रेसी बॉटम-अप है। दोनों मिलकर डिजिटल शासन को पूरा करते हैं।

ई-गवर्नेंस के लाभ और चुनौतियाँ

लाभ:

पारदर्शिता, भ्रष्टाचार में कमी, समय और लागत की बचत, 24x7 सेवाएँ।

चुनौतियाँ:

डिजिटल विभाजन (ग्रामीण-शहर की पहुँच), साइबर सुरक्षा खतरे, उच्च प्रारंभिक निवेश और डिजिटल साक्षरता का अभाव।

भारत में ई-गवर्नेंस के प्रमुख उदाहरण

डिजिटल इंडिया, उमंग (UMANG) ऐप, ई-होस्पिटल, ई-कोर्ट, भारत कोष (Bharatkosh) और जीआईएस (GIS) आधारित सेवाएँ प्रमुख हैं। आधार और डिजीलॉकर ने पहचान एवं दस्तावेज साझाकरण को सरल बनाया। सीएससी (CSC) ग्रामीण क्षेत्रों में ई-सेवा केंद्र हैं।

Government efforts to encourage citizen participation-

डिजिटल इंडिया पहल (Digital India Initiative)

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार ने ऑनलाइन सेवाओं को हर नागरिक तक पहुँचाया है। इसके माध्यम से डिजीलॉकर, ई-हस्ताक्षर और सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। नागरिक अब बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, घर बैठे सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह पहल पारदर्शिता और सहभागिता बढ़ाने में सहायक है।

माईगॉव पोर्टल (MyGov Portal)

MyGov Portal नागरिकों की राय को सरकार तक पहुँचाने का मंच है।
माईगॉव (MyGov) एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ नागरिक सरकारी नीतियों और योजनाओं पर अपने सुझाव दे सकते हैं। यहाँ विभिन्न विषयों पर चर्चा, सर्वेक्षण और प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। नागरिकों के विचारों को नीति-निर्माण में शामिल किया जाता है। इस प्रकार यह पोर्टल ई-डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाता है।

ई-वोटिंग और ई-परामर्श (E-Voting & E-Consultation)

सरकार ने चुनाव प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए ई-वोटिंग मशीनों (EVM) और रिमोट वोटिंग की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसके अलावा विभिन्न विभाग ऑनलाइन सार्वजनिक परामर्श (Public Consultation) आयोजित करते हैं, जहाँ कोई भी नागरिक विधेयक या नियम पर अपनी राय दे सकता है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आम नागरिक की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है।

सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) – ग्रामीण भागीदारी

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के द्वार हैं। ये केंद्र नागरिकों को ऑनलाइन फॉर्म भरने, शुल्क जमा करने और सरकारी योजनाओं से जुड़ने में मदद करते हैं। ग्रामीण नागरिक जो डिजिटल रूप से कम सक्षम हैं, वे सीएससी के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। यह पहल डिजिटल विभाजन को कम करती है और समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करती है।

ओपन डेटा प्लेटफॉर्म (डेटा.gov.in)

डेटा.gov.in पोर्टल पर सरकार विभिन्न विभागों का खुला डेटा (Open Data) सार्वजनिक करती है। नागरिक, शोधकर्ता और पत्रकार इस डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और सरकार को सुझाव दे सकते हैं। यह पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और नागरिकों को सूचना के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार खुला डेटा नागरिक भागीदारी का एक महत्वपूर्ण साधन है।

PPP मॉडल (Public-Private Partnership)

PPP मॉडल सरकार और निजी कंपनियों के बीच साझेदारी है, जिसमें दोनों मिलकर सार्वजनिक सेवाएँ या इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करते हैं। इसमें निजी क्षेत्र पूंजी, तकनीक और दक्षता लाता है, जबकि सरकार नीतिगत सहायता और जमीन प्रदान करती है। इस मॉडल का उद्देश्य सरकार पर वित्तीय बोझ कम करना और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना है। उदाहरण: टोल रोड, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, डिजिटल इंडिया के कुछ घटक।

PPP मॉडल के मुख्य प्रकार

BOT (Build-Operate-Transfer)

में निजी कंपनी बनाकर चलाती है, फिर सरकार को हस्तांतरित करती है।

BOOT (Build-Own-Operate-Transfer)

में कंपनी कुछ समय तक स्वामित्व रखती है।

DBFOT (Design-Build-Finance-Operate-Transfer)

में डिजाइन से लेकर संचालन तक निजी भागीदारी होती है।

O&M (Operate & Maintain)

में सरकार बनाती है, निजी कंपनी केवल संचालन और रखरखाव करती है।

IT और ई-गवर्नेंस में PPP मॉडल का महत्व

सरकार अकेले बड़े IT इंफ्रास्ट्रक्चर (डेटा सेंटर, क्लाउड सर्वर) में निवेश नहीं कर सकती, इसलिए PPP मॉडल अपनाया जाता है। निजी कंपनियाँ तकनीक, मेंटेनेंस और साइबर सुरक्षा प्रदान करती हैं। उदाहरण: CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) PPP मॉडल पर चलते हैं। इससे सरकारी सेवाएँ तेज़, सस्ती और बेहतर बनती हैं।

PPP मॉडल के लाभ

निजी क्षेत्र की तकनीकी दक्षता और नवाचार से परियोजनाएँ जल्दी पूरी होती हैं। सरकार पर वित्तीय बोझ कम होता है क्योंकि निजी कंपनी पूंजी लगाती है। सेवाओं की गुणवत्ता और रखरखाव बेहतर होता है। इससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिलती हैं और सरकार का जोखिम कम हो जाता है।

PPP मॉडल की चुनौतियाँ

निजी कंपनी मुनाफे पर केंद्रित होती है, जिससे गरीब नागरिकों के लिए सेवाएँ महँगी हो सकती हैं। सरकार और निजी कंपनी के बीच अनुबंधों में विवाद और कानूनी जटिलताएँ आम हैं। लंबी

परियोजनाओं में समय सीमा और लागत बढ़ने का जोखिम रहता है। पारदर्शिता की कमी से भ्रष्टाचार की संभावना भी बनी रहती है।

MP ऑनलाइन सेवा का परिचय

MP ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख ई-गवर्नेंस पहल है। यह नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। यह पोर्टल सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के बीच PPP मॉडल पर कार्य करता है। इसका उद्देश्य नागरिकों को किसी भी समय, कहीं भी सेवाएं उपलब्ध कराना है। पोर्टल का मुख्य लिंक www.mponline.gov.in है ।

MP ई-सेवा पोर्टल की मुख्य विशेषताएँ

MP ई-सेवा पोर्टल 56 विभागों की 1700 से अधिक सेवाओं को एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराता है। इसमें सिंगल साइन-ऑन (SSO) सुविधा है, जिससे एक बार लॉगिन करके सभी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। पोर्टल को मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध कराया गया है। यह आधार आधारित प्रमाणीकरण और डिजिटल प्रमाणपत्रों से सुरक्षित है।

MP ऑनलाइन पर उपलब्ध प्रमुख सेवाएँ

इस पोर्टल पर जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज़ ऑनलाइन बनवाए जा सकते हैं । शिक्षा से संबंधित प्रवेश फॉर्म, बोर्ड परीक्षा फॉर्म और अंकसूची सत्यापन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा बिजली बिल भुगतान, भू-अभिलेख (भूलेख) डाउनलोड और व्यापम भर्ती फॉर्म जैसी सुविधाएँ भी शामिल हैं।

MP ऑनलाइन के लाभ

MP ऑनलाइन सेवाएँ 24×7 उपलब्ध रहती हैं, जिससे नागरिक छुट्टी के दिन भी आवेदन कर सकते हैं। हर आवेदन को ट्रैक करने के लिए एक आवेदन ID मिलती है, जिससे रियल-टाइम स्टेटस देखा जा सकता है। यह पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस प्रक्रिया है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

UIDAI और आधार का परिचय (Unique Identification Authority of India)

UIDAI भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक प्राधिकरण है, जो 12 अंकों का आधार नंबर जारी करता है। यह नंबर प्रत्येक नागरिक के लिए अद्वितीय (Unique) होता है और नागरिकता या डोमिसाइल का प्रमाण नहीं होता। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की पहचान को डिजिटल रूप से सत्यापित करना है। आधार सेवाओं का संचालन UIDAI के डाटा सेंटर्स (CIDR) के माध्यम से होता है ।

आधार सेवा केंद्र पर उपलब्ध सेवाएँ (Aadhaar Seva Kendra) - ASK

आधार सेवा केंद्र सभी आधार संबंधी सेवाओं के लिए एक-स्टॉप स्थान है, जो वातानुकूलित और व्हीलचेयर फ्रेंडली वातावरण प्रदान करता है । यहाँ नए आधार के लिए नामांकन (Enrolment),

नाम, पता, मोबाइल नंबर जैसी जनसांख्यिकीय जानकारी का अपडेट किया जा सकता है । साथ ही फोटो, उंगलियों के निशान और आँख की पुतली (Iris) जैसी बायोमेट्रिक जानकारी भी अपडेट की जा सकती है। 5 और 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट भी यहाँ कराया जाता है ।

आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication)

आधार प्रमाणीकरण वह प्रक्रिया है, जिसमें नागरिक द्वारा दी गई जानकारी का मिलान UIDAI के केंद्रीय डेटाबेस (CIDR) से किया जाता है । यह प्रमाणीकरण तीन तरीकों से किया जा सकता है: डेमोग्राफिक (नाम, पता), बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान या आईरिस) और OTP आधारित (मोबाइल पर भेजे गए कोड के माध्यम से) । सुरक्षा बढ़ाने के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (दो या अधिक तरीकों का संयोजन) का भी उपयोग किया जा सकता है। बैंक, टेलिकॉम कंपनियाँ जैसी संस्थाएँ (AUA) इस सेवा का उपयोग करती हैं ।

आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी (Paperless Offline e-KYC)

यह एक वैकल्पिक और स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसमें बिना इंटरनेट और बिना बायोमेट्रिक दिए पहचान सत्यापित की जा सकती है । नागरिक UIDAI पोर्टल से एक XML फ़ाइल या QR कोड डाउनलोड करता है, जो UIDAI द्वारा डिजिटली साइन होता है । इस फ़ाइल को शेयर फ्रेज (पासवर्ड) से एन्क्रिप्ट किया जाता है, जिसे नागरिक एजेंसी के साथ साझा करता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नागरिक का पूरा आधार नंबर नहीं दिखता, बल्कि एक रेफरेंस ID शेयर होती है, जिससे गोपनीयता बनी रहती है ।

नई सुविधाएँ और भविष्य (Aadhaar App)

UIDAI नया आधार ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जो पेपरलेस पहचान साझाकरण को और सरल बना देगा । इस ऐप में नागरिक अपने परिवार के 5 सदस्यों का आधार डेटा रख सकेंगे और उसमें से केवल चुनिंदा जानकारी (सेलेक्टिव डेटा) साझा करने का विकल्प होगा । इसमें वन-क्लिक बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक जैसी सुरक्षा सुविधाएँ भी होंगी। होटल चेक-इन, सोसाइटी एंट्री जैसे स्थानीय उपयोगों के लिए ऑफलाइन फेस वेरिफिकेशन की सुविधा भी दी जाएगी ।

UMANG ऐप – (Unified Mobile Application for New-age Governance)

UMANG भारत सरकार का एक ऑल-इन-वन मोबाइल ऐप है । यह केंद्र और राज्य सरकारों की 1,700 से अधिक सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है । इसे नीति आयोग और मीनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी (MeitY) द्वारा विकसित किया गया है । इस ऐप पर आधार, पैन, पासपोर्ट, ईपीएफओ, गैस सिलेंडर बुकिंग, पंजीकृत मोबाइल नंबर ब्लॉक करने जैसी सेवाएँ उपलब्ध हैं । UMANG ऐप 13 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है और इसका उपयोग Android, iOS तथा वेब पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है ।

UMANG ऐप की विशेषताएँ और लाभ

UMANG ऐप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता "सिंगल साइन-ऑन (SSO)" है, यानी एक बार लॉगिन करने के बाद बिना बार-बार लॉगिन किए सभी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है । यह ऐप आधार

आधारित प्रमाणीकरण, OTP और डिजिटल सिग्नेचर जैसे सुरक्षित तरीकों को सपोर्ट करता है । इसके अलावा इसमें इन-ऐप पेमेंट गेटवे, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज और अपॉइंटमेंट बुकिंग जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं । नागरिकों को अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे डिवाइस की मेमोरी और समय दोनों की बचत होती है।

डिजिटल लॉकर (DigiLocker) – पेपरलेस दस्तावेज़ भंडारण

DigiLocker भारत सरकार का एक क्लाउड-बेस्ड डिजिटल वॉलेट है, जो नागरिकों को 1 GB तक की मुफ्त ऑनलाइन स्टोरेज सुविधा प्रदान करता है । इसमें आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, शैक्षिक प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी जैसे दस्तावेज़ सुरक्षित रूप से अपलोड किए जा सकते हैं । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी विभाग (जैसे परिवहन, शिक्षा बोर्ड) सीधे नागरिक के DigiLocker में ई-दस्तावेज़ (signed documents) भेज सकते हैं। इन डिजिटल दस्तावेज़ों को कानूनी तौर पर मूल दस्तावेज़ों के समान ही मान्यता प्राप्त है और इन्हें कभी भी, कहीं भी साझा या डाउनलोड किया जा सकता है।

DigiLocker की प्रमुख विशेषताएँ

DigiLocker सीधे आधार नंबर से लिंक होता है, इसलिए इसमें लॉगिन करने के लिए आधार OTP या मोबाइल OTP का उपयोग किया जाता है । इसमें "Issued Documents" नामक सेक्शन होता है जहाँ सरकारी विभागों द्वारा जारी प्रमाणपत्र सीधे आते हैं, जिससे जालसाजी की संभावना नहीं रहती । नागरिक अपने स्वयं के स्कैन किए गए दस्तावेज़ों पर ई-साइन (Aadhaar eSign) कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है । यह सेवा पूरी तरह मुफ्त है और इसका मोबाइल ऐप Android और iOS दोनों पर उपलब्ध है । DigiLocker का उपयोग यातायात पुलिस चेकिंग, बैंक KYC, एयरपोर्ट एंट्री आदि में किया जा सकता है ।

डिजिटल लाइब्रेरी (Digital Library)

डिजिटल लाइब्रेरी एक ऑनलाइन प्रणाली है जहाँ पुस्तकों, शोध पत्रों, पत्रिकाओं और मैन्युस्क्रिप्ट्स का डिजिटल रूप (e-books, PDF) संग्रहीत किया जाता है । भारत में प्रमुख डिजिटल लाइब्रेरी में NDLI (National Digital Library of India), e-PG Pathshala, Swayam, और विभिन्न राज्यों की ई-लाइब्रेरी शामिल हैं । NDLI 70 से अधिक भाषाओं में 7 करोड़ से अधिक अकादमिक संसाधन प्रदान करती है और इसे IIT खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया है । डिजिटल लाइब्रेरी कभी बंद नहीं होती (24×7 उपलब्ध), कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है, और पुस्तकें खराब या चोरी नहीं हो सकतीं । इसमें कीवर्ड सर्च, बुकमार्क, हाइलाइटिंग और ऑडियो-विजुअल कंटेंट जैसी उन्नत सुविधाएँ भी होती हैं ।

साइबर अपराध (Cyber Crime)

साइबर अपराध (Cyber Crime)

साइबर अपराध वह अपराध है जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल डिवाइस का उपयोग अपराध के साधन या लक्ष्य के रूप में किया जाता है। यह पारंपरिक अपराधों (चोरी, धोखाधड़ी) का डिजिटल संस्करण है, लेकिन इसमें अपराधी की पहचान छिपाना आसान होता है। साइबर अपराध भौगोलिक सीमाओं से परे होता है और इसके साक्ष्य डिजिटल होते हैं। भारत में साइबर अपराधों की जांच के लिए साइबर सेल और IT एक्ट 2000 जैसे कानून मौजूद हैं।

तेजी से बढ़ता इंटरनेट उपयोग और डिजिटल पेमेंट का चलन साइबर अपराधियों को आसान शिकार देता है। अधिकांश लोग कमजोर पासवर्ड, पब्लिक वाई-फाई का उपयोग और अनसेफ वेबसाइटों पर क्लिक करने जैसी गलतियाँ करते हैं। साइबर अपराधी नए-नए तरीके (जैसे AI आधारित फर्जी वॉयस कॉल) अपनाते रहते हैं, जिनसे आम जनता अनजान होती है। इसके अलावा साइबर कानूनों का कमजोर प्रवर्तन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों को पकड़ने में कठिनाई भी बड़े कारण हैं।

साइबर अपराध से बचाव के उपाय

हमेशा मजबूत और अनोखे पासवर्ड (अपरकेस, लोअरकेस, नंबर, सिंबल का मिश्रण) का उपयोग करें और दो-चरणीय सत्यापन (2FA) चालू रखें। कभी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अनजान कॉल/ईमेल पर बैंकिंग जानकारी साझा करें। अपने सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस और ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें। सार्वजनिक वाई-फाई पर बैंकिंग न करें और अपने डेटा का नियमित बैकअप जरूर लें। किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पोर्टल या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (1930) पर करें।

. ईमेल फ्रॉड (Email Fraud)

ईमेल फ्रॉड एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें अपराधी नकली ईमेल भेजकर पीड़ित को ठगता है। इसमें आमतौर पर नकली लॉटरी, नौकरी के झूठे ऑफर या बैंक अकाउंट अपडेट जैसे लालच दिए जाते हैं। पीड़ित से व्यक्तिगत जानकारी या पैसे ट्रांसफर करने का अनुरोध किया जाता है। इसे रोकने के लिए अनजान ईमेल पर क्लिक न करें और कभी भी ईमेल के माध्यम से संवेदनशील जानकारी साझा न करें।

फिशिंग (Phishing) नकली वेबसाइटों से जानकारी चोरी

फिशिंग एक साइबर हमला है जिसमें अपराधी बैंक, गवर्नमेंट या किसी प्रसिद्ध कंपनी की नकली वेबसाइट या ईमेल बनाता है। पीड़ित को उस नकली लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जहाँ वह अपना यूजरनेम, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल डाल देता है। यह जानकारी सीधे अपराधी के पास चली जाती है, जिसका उपयोग वह धोखाधड़ी के लिए करता है। फिशिंग से बचने के लिए हमेशा URL (वेबसाइट एड्रेस) को ध्यान से देखें और कभी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें।

स्पूफिंग (Spoofing) – नकली पहचान बनाना

स्पूफिंग में अपराधी अपनी पहचान छिपाने के लिए किसी विश्वसनीय स्रोत (जैसे बैंक, पुलिस, या जाना-पहचाना मोबाइल नंबर) का नकली रूप बनाता है। ईमेल स्पूफिंग में अपराधी का ईमेल एड्रेस आपको किसी और का दिखता है, जबकि कॉल स्पूफिंग में फोन पर किसी आधिकारिक नंबर का नाम दिखता है। इसका उद्देश्य पीड़ित का भरोसा जीतकर उससे पैसे या जानकारी ऐंठना होता है। स्पूफिंग से बचाव के लिए बिना सत्यापन के कभी भी फोन या ईमेल पर संवेदनशील जानकारी न दें।

हैकिंग (Hacking)– अनधिकृत पहुँच बनाना

हैकिंग का अर्थ है बिना अनुमति के किसी व्यक्ति या संस्था के कंप्यूटर, अकाउंट या डिवाइस में घुसपैठ करना। हैकर विभिन्न तकनीकों जैसे कमजोर पासवर्ड तोड़ना, मैलवेयर डालना या सॉफ्टवेयर की कमियों (Vulnerabilities) का फायदा उठाना आदि का उपयोग करते हैं। हैकिंग के उद्देश्य डेटा चोरी, रैंसमवेयर हमला, जासूसी या केवल सिस्टम को नुकसान पहुँचाना हो सकते हैं। भारत में हैकिंग IT एक्ट 2000 के तहत एक दंडनीय अपराध है, जिसमें तीन साल तक की सजा हो सकती है।

आइडेंटिटी थेफ्ट (Identity Theft)– पहचान चोरी

आइडेंटिटी थेफ्ट में अपराधी किसी दूसरे व्यक्ति का आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या बैंक डिटेल्स चुराकर उसकी पहचान का दुरुपयोग करता है। चुराई गई पहचान का उपयोग फर्जी लोन लेने, क्रेडिट कार्ड जारी करने, नकली पैन कार्ड बनाने या अन्य अपराध करने में किया जाता है। पीड़ित को तब पता चलता है जब उसके नाम पर बैंक से रिकवरी कॉल आती है या उसकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाती है। बचाव के लिए कभी भी आधार, पैन या बैंक डिटेल्स किसी अनजान व्यक्ति या वेबसाइट से साझा न करें और अपने बैंक स्टेटमेंट की नियमित जांच करते रहें।

University Exam Questions-

UNIT-I (E-governance, E-democracy, Cyber Crime & Security)

E-governance & E-democracy (ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएं):

1. ई-गवर्नेंस (E-governance) क्या है? ई-गवर्नेंस द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का वर्णन कीजिए। (D.C.A. - June 2023)

2.ई-गवर्नेन्स से क्या तात्पर्य है? वर्णन कीजिए। (D.C.A. - June 2023)

3.ई-शासन के घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। (D.C.A. - Feb 2019 / May/June 2019)

4.उदाहरण के साथ ई-गवर्नेंस की G2C (गवर्नमेंट टू सिटीजन) सेवा की व्याख्या कीजिए। (D.C.A. - Feb 2019 / May/June 2019)

5.ई-गवर्नेंस क्या है? नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के प्रयासों की व्याख्या कीजिए। (D.C.A. - Feb 2019)

6.शिक्षा में पीपीपी (PPP) मॉडल क्या है? (PGDCA - May/June 2019)

7.डिजिटल लॉकर (Digital Locker) क्या है? इसकी क्या आवश्यकता है? (D.C.A. - June 2023)

8.टिप्पणी लिखिए: (क) ई-गवर्नेंस (ख) ई-डेमोक्रेसी (D.C.A. - Jan 2019)

9.टिप्पणी लिखिए: ई-डेमोक्रेसी (D.C.A. - Feb 2019)

Cyber Crime & Security (साइबर अपराध और सुरक्षा):

1. साइबर अपराध (Cyber Crime) को विस्तार से समझाइए। साइबर अपराध में होने वाले विभिन्न प्रकार के हमलों को भी समझाइए। (D.C.A. - June 2023)

2. साइबर क्राइम क्या होता है? उदाहरण सहित समझाइए। (D.C.A. - Feb 2019)

3. स्पायवेयर (Spyware) एवं मैलवेयर (Malware) का वर्णन कीजिए। (D.C.A. - June 2023)

4.फिशिंग (Phishing) एवं स्पूफिंग (Spoofing) अटैक को समझाइए। (D.C.A. - June 2023)

5.Denial of Service को समझाइए। (PGDCA - May/June 2019)

6.इनफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट को उदाहरण सहित समझाइए। (D.C.A. - Jan 2019)

7.टिप्पणी लिखिए: (i) इनफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट (ii) साइबर क्राइम (D.C.A. - Feb 2019)

Questions for DCA paper – unit1 IT trends

** मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता को समझाइए। (D.C.A. - June 2023)*

*मल्टीमीडिया की विशेषताओं और उपयोगों को परिभाषित करें। डिजिटल वीडियो और उनके प्रसंस्करण के तरीके समझाइए। (D.C.A. - June 2023)

** मल्टीमीडिया की रोज के दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है? (D.C.A. - Jan 2019)*

*मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया के विभिन्न सॉफ्टवेयरों की व्याख्या कीजिए। (D.C.A. - Feb 2019)

** मल्टीमीडिया क्या है? विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया को उनके उपयोग के आधार पर समझाइए। (D.C.A. - Feb 2019)*

*मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या हैं? (D.C.A. - Feb 2019 / May/June 2019)

** टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के फोंट का वर्णन करें। (D.C.A. - June 2023)*

*मल्टीमीडिया में ध्वनि का क्या महत्व है ? मल्टीमीडिया में मोना और स्टीरियो ध्वनि के बीच में अंतर करो। (D.C.A. - June 2023)

** वर्चुअल वास्तविकता का वर्तमान में क्या उपयोग है? विस्तार से समझाइए। (D.C.A. - Jan 2019)*

*वर्चुअल रियलिटी की विस्तार से व्याख्या कीजिए। वर्चुअल रियलिटी के उपयोगों को भी समझाइए। (D.C.A. - Feb 2019)

** वर्चुअल रियलिटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, एवं इसके उपयोग भी लिखिए। (D.C.A. - Feb 2019)*

*मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण क्या हैं? (D.C.A. - Feb 2019 / May/June 2019)

** वीडियो फाइलों पर एक नोट लिखिए। वीडियो फाइलों के स्वरूपों का भी वर्णन कीजिए। (D.C.A. - Feb 2019 / May/June 2019)*

*मिडी (संगीतकार संगीत वाद्ययंत्र डिजिटल इंटरफेस) की अवधारणा को समझाइए। (D.C.A. - Feb 2019)

** मिडी (म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल[illegible] इंटरफेस) की अवधारणा को समझाइए। (D.C.A. - May/June 2019)*

*डिस्ट्रिब्यूटेड सिस्टम से आप क्या समझते हैं? डिस्ट्रिब्यूटेड सिस्टम के फायदे और नुकसान लिखिए। (D.C.A. - Jan 2019)

** डिस्ट्रिब्यूटेड सिस्टम क्या होता है? डिस्ट्रिब्यूटेड सिस्टम के फायदे और नुकसान लिखिए। (D.C.A. - Jan 2019)*

*डिस्ट्रिब्यूटेड सिस्टम क्या है? इसके फायदे और नुकसानों की व्याख्या कीजिए। (D.C.A. - Feb 2019)

** डिस्ट्रिब्यूटेड सिस्टम क्या होता है? इसके लाभ एवं हानियों के साथ विस्तार से बताइए। (D.C.A. - Feb 2019)*

*इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट डिजिटल डिवाइड क्या है? समझाइए। (D.C.A. - Feb 2019)